अब्दुल कादिर शमसुददीन बुबेर

वी.

माधव प्रभाकर ओक

(के. एन. वांचौ, के. सी. दास गुप्ता और जे.सी.शाह, जे.जे.)

मध्यस्थता-विवाद के विषय में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया-यदि विवाद को संदर्भित किया जा सकता है-मध्यस्थता-खातों के लिए पूछना-यदि धोखाधड़ी का आरोप है-मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (1940 का X), एस. 20.

अपीलार्थी बी और उत्तरदाता ओ और ए के बीच वन के संबंध में एक समझौता किया गया था। ओ और ए के अलावा एक अन्य व्यक्ति को भी उक्त जंगल में दिलचस्पी थी। उक्त समझौते में उल्लिखित वन के संबंध में पहले की गई अन्य सहमति का उल्लेख किया गया है। समझौते का परिचालन भाग इन शर्तों में थाः-

इस समझौते के संबंध में या दिनांक 22.10.1948 और 5.5.1952 के समझौतों के संबंध में या खान बहादुर दिवाकर के पैसे या जंगल काटने या निर्यात या किसी अन्य तरीके से पक्षकारान के बीच कोई विवाद हो, तो

उसे मिल जाना चाहिए। मध्यस्थों की नियुक्ति और उनके माध्यम से वर्तमान कानून अनुसार निर्णय लिया गया।"

अपीलकर्ता बी और उत्तरदाताओं ओ और ए के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। उत्तरदाताओं ने खातों और प्राप्तकर्ता की नियुक्ति सहित राहत के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 20 के तहत एक आवेदन दायर किया।

आवेदन का अपीलकर्ता बी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया था कि चूंकि जंगल में रुचि रखने वाला व्यक्ति आवेदन में पक्षकार नहीं था, इसलिए मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो विवाद करता है, जंगल मध्यस्थ के समक्ष नहीं होगा और आगे, क्योंकि धोखाधड़ी के आरोप थे जो विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं करने का एक आधार था।

माना जाता कि 'जहां पार्टियों ने मध्यस्थता समझौते में प्रवेश किया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि कोई अन्य व्यक्ति भी रुचि रखता है, लेकिन उसे छोड़ दिया, तो अदालत को पार्टियों को उनके द्वारा चुने गए मंच पर भेजना चाहिए, भले ही दूसरे व्यक्ति को, जो वास्तव में हितधारक हो, और जिसका हिस्सा विवाद में नहीं था, मध्यस्थ के समक्ष पार्टी नहीं बनाया जा सकता है।

जहां वह एक व्यक्ति का हिस्सा, मध्यस्थ के समक्ष कोई पक्ष नहीं था, विवाद में नहीं था, इस आधार पर विवाद को मध्यस्थता के लिए

संदर्भित करने पर कोई रोक नहीं हो सकती है कि पूरा विवाद मध्यस्थ के समक्ष नहीं था। मध्यस्थ पक्षों के बीच विवाद का निर्णय उसके समक्ष करेगा। उस व्यक्ति के हिस्से को छोड़कर एक पुरस्कार देती है जो उससे पहले एक पक्षकार नहीं था।

इसके अलावा, माना गया कि जब किसी पार्टी के खिलाफ धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए थे और जिस पार्टी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, वह चाहती थी कि मामले की सुनवाई खुली अदालत में की जाए, तो यह अदालत के लिए पर्याप्त कारण होगा। एक मध्यस्थता समझौते को दाखिल करने के लिए, न कि कोई संदर्भ देने के लिए। लेकिन यह हर आरोप नहीं है कि विशेष रूप से खातों के मामले में किसी प्रकार की बेईमानी का आरोप लगाया जाए, यह आरोप लगाया जाए कि वे सही नहीं थे या कुछ वस्तुओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था या ऐसे आरोप जो खाते रखने के मामले में नैतिक बेईमानी या नैतिक कदाचार का सुझाव देते हों या संकेत करते हों। धोखाधड़ी के ऐसे गंभीर आरोप जो अदालत को मध्यस्थता समझौते को दायर करने का आदेश देने से इनकार करने और संदर्भ देने से इनकार करने और मामले को उस मंच से बाहर ले जाने के लिए बाध्य करेंगे जिसे पार्टियों ने स्वयं चुना है।

मौजूदा मामले में, यह नहीं कहा जा सकता कि वांछित संदर्भ टुकड़ों में था और कार्रवाई के कारण को विभाजित कर दिया था। उठाया गया

विवाद मध्यस्थता खंड द्वारा कवर किया गया था, और धोखाधड़ी का ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं था ऐसा कहें जो अदालत के लिए मध्यस्थता के लिए संदर्भित न करने का पर्याप्त कारण था।

ओबिटर. मुफस्सिल अदालतों में पैरवी पर बहुत सख्ती से विचार नहीं किया जा सकता था।

रसेल बनाम। रसेल, [1880] 14 Ch. डी. 471, चर्चा की गई।

चार्ल्स ओसेनशन एंड कंपनी वी। जॉनस्टन, [1942] ए. सी. 130, महाराजा सर मनिंद्र चंद्र नंदी बनाम। एच. वी. लो एंड कं., लिमिटेड। ए. आई. आर. 1924 कैल. 796, नरसिंह प्रसाद बूबनर बनाम। धनराज मिल्स, आई. एल. आर. (1942) 21 पट। 544, भारत संघ बनाम। फर्म विश्वधा घी व्यापर मंडल, आई. एल. आर. (1953) 1 सभी। 423, सुधांगसु भट्टाचार्जी बनाम। रूपलेखा पिक्चर्स, ए. आई. आर. 1954 कैल. 281 और मैनिफिया वी। रेलवे यात्रियों का आश्वासन एंसे कं. (1881) 44 एल. टी. 552, संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 305/ 1958

दिनांकित निर्णय और डिक्री से अपील 14,15 अप्रैल,1955 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 28/1955

एस. बी. सुखथंकर, एस. एन. एंडले, रामेश्वर नाथ और पी. एल. वोहरा, अपीलार्थी के आदेश संख्या 28 से अपील। की ओर से। ए. वी. विश्वनाथ शास्त्री और गणपत राय, उत्तरदाताओं।

20 सितंबर 1961 का निर्णय न्यायालय द्वारा दिया गया था

वांचो, जे.-यह एक प्रमाण पत्र पर एक अपील है जो बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया। एक अनुप्रयोग यह एस के तहत दायर किया गया था। 20 मध्यस्थता ए. ओ. टी, नहीं। 1940 का एक्स। (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) अपीलार्थी के विरुद्ध दो प्रत्यर्थियों द्वारा प्रार्थना करें कि मध्यस्थता समझौता दिनांकित हो 27 फरवरी, 1953 को अदालत में दायर किया जा सकता है, मध्यस्थता तदनुसार बनाया जाए, और उसके बाद एक डिक्री मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय की शर्तें पास हो गया।

जिन परिस्थितियों में आवेदन किया गया था वे ये थीं। डोन गांव में एक जंगल है, जो तीन व्यक्तियों का था, अर्थात्, माधव प्रभाकर ओक, प्रतिवादी नंबर एल, (बाद में इसे ओक के रूप में संदर्भित किया गया), बाबाजी चंद्रराव राणे, दूसरे प्रतिवादी के चाचा (इसके बाद बाबाजी के रूप में संदर्भित), गजानन बाबाजी राणे (बाद में गजानन कहा जाएगा)। जंगल में ओक का छह आने का हिस्सा था, बाबाजी का आठ आने का हिस्सा था और गजानन का दो आने का हिस्सा था। उल्लेखनीय है कि गजानन का

हिस्सा अपीलकर्ता ने नवंबर 1944 में खरीदा था। 22 अक्टूबर, 1948 को जंगल काटने के लिए बाबाजी, ओक और अपीलकर्ता के बीच एक साझेदारी समझौता हुआ। तीन मालिकों के लिए जंगल का मूल्य रुपये निर्धारित किया गया था। 60,000/- जो उनके बीच उनके शेयरों के अनुसार विभाजित किया जाना था। कटाई का कार्य अपीलकर्ता द्वारा किया जाना था जो एक अनुभवी वन ठेकेदार प्रतीत होता है। कटाई में किए गए व्यय और जंगल के मूल्य से अधिक की कोई भी आय तीन भागीदारों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी; यदि कोई हानि होती थी तो उसे भी उन्हें समान रूप से वहन करना पड़ता था। हालाँकि, ऐसा प्रतीत होता है कि इस समझौते के अनुसरण में कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि स्पष्ट रूप से एक मुकदमा दो व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया था, जिनके साथ इसी जंगल को काटने के बारे में 1939 का पूर्व समझौता हुआ था।ऐसा भी प्रतीत होता है कि मार्च 1951 में गजानन और अपीलकर्ता ने एक अन्य दस्तावेज़ निष्पादित किया जिसमें अपीलकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली गजानन के हिस्से की कीमत बढ़ा दी गई थी। मई 1951 में बाबाजी की मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप मई 19o2 में अपीलकर्ता और बाबाजी के उत्तराधिकारियों, अर्थात् अनंत यशवंत राणे प्रतिवादी नंबर 2 (बाद में अनंत के रूप में संदर्भित), अंबिकाबाई, बाबाजी की विधवा, गजानन और उनकी मां देवूबाई और ओक के बीच एक और समझौता निष्पादित किया गया।

यह समझौता 1948 के पहले के समझौते को संदर्भित करता है और स्पष्ट रूप से बाबाजी की मृत्यु के कारण इसकी आवश्यकता थी। इसने उस समझौते की पुष्टि की और कहा कि इसे 1948 के समझौते में अनंत, अंबिकाबाई और देवूबाई को समझौते में पक्ष बनाने की आवश्यकता के कारण तैयार किया गया था। रुपये का विचार। 60,000/- मालिकों के बीच विभाजित किया गया था, और 51,000/- रुपये ओक, अनंत और अंबिकाबाई को दिए जाने थे और बाकी उस कीमत का प्रतिनिधित्व करते थे जिसके लिए अपीलकर्ता ने गजानन और उनकी मां देवूबाई का हिस्सा खरीदा था। ऐसा लगता है कि इस समझौते के अनुपालन में भी कुछ नहीं किया गया है। अक्टूबर 1952 में, अपीलकर्ता, दो प्रतिवादियों और एक खान बहादुर दिवकर के बीच एक और समझौता हुआ जिसके द्वारा जंगल काटने का काम दिवकर को रुपये की राशि के लिए सौंपा गया था। 1,00,000/-. यह राशि अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच विभाजित की जानी थी; अनंत को रुपये मिलने थे. 44,800/-, ओक रु. 35,700/- और अपीलकर्ता को रु. 19,500/-. दिवकर इस समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने में असमर्थ थे। अंततः 27 फरवरी, 1953 को अपीलकर्ता और दोनों उत्तरदाताओं के बीच एक समझौता हुआ क्योंकि दिवकर ने अपने समझौते का पालन नहीं किया था। दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति हुई कि दिवकर के साथ विवाद का फैसला किया जाएगा और

जंगल को 22 अक्टूबर, 1948 और 5 मई, 1952 के समझौतों के अनुसार काटा जाएगा। इस समझौते के ऑपरेटिव हिस्से में मध्यस्थता के लिए एक शब्द भी शामिल था। सी.एल. 6(4), जो इन शब्दों में है:-

(1) में यह निवेदन किया गया है कि अंबिका बाई का इस जंगल में हिस्सा है और उसको इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया है। धारा 20 के तहत उसे रेफर नहीं किया जा सकता है क्योंकि पूरा विवाद ही 22-10-1948 के एग्रीमेंट के तहत उत्पन्न हुआ है जो कि आर्बिट्रेटर के समक्ष उत्पन्न नहीं किया जा सकता । इस तर्क को विचारण न्यायालय ने संदर्भित माना परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा इसे खारिज करते हुए कहा कि अंबिका बाई का हित आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के तहत पर्याप्त रूप से अनन्त के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है और ऐसा है तो आर्बिट्रेशन समझौते के तहत इस पर आपत्ति नहीं ली जा सकती, इसके होते हुए हमारी राय में ऐसा कोई हालात नहीं है कि आर्बिट्रेशन को यह विवाद नहीं दिया जा सके जैसाकि 27/02/1953 के समझौते के क्लॉज में है। यशवंत बाबाजी के भाई हैं और अनंत उनका बेटा है इस पर विवाद नहीं है कि संयुक्त परिवार की ओर से बाबाजी का आठ प्रतिशत जंगल में हिस्सा है और उनका आधा हिस्सा भी है जो कि चार प्रतिशत है। उनकी मृत्यु पर इनका शेयर उनकी विधवा अंबिका बाई को जाता है जबकि अनन्त को बचा हुआ आधा हिस्सा जाता है। अनन्त इस परिवार में सबसे बडा जीवित सदस्य है अत: हाईकोर्ट ने यह सही

प्रतिपादित किया कि अनंत संयुक्त परिवार के संपूर्ण हित को प्रतिवेदित करता है जो कि जंगल में आठ प्रतिशत आता है । ऐसा न होते हुए भी अंबिका बाई जो कि 05/05/1952 के समझौते के तहत इसका पक्षकार थी । हमें ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती कि अपीलांट व प्रत्यर्थी के बीच का विवाद आर्बिट्रेशन को क्यों नहीं दिया जा सकता । जैसाकि पूर्व से विदित है कि अंबिकाबाई का हिस्से का कोई विवाद नहीं है अंबिकाबाई 27/02/1953 वाले समझौते की पार्टी नहीं थी जबकि 05/05/1952 वाले समझौते की पक्षकार थी । अपीलार्थी मई 1952 के समझौते के पक्षकार थे और यह जानते थे कि उस जंगल में अंबिकाबाई का हिस्सा है इसके बावजूद भी अपीलार्थी ने 27/02/1953 को दो प्रत्यर्थियों के साथ समझौता कर यह तय किया कि विवाद जो होगा वह रेस्पोंडेंट के साथ आर्बिट्रेशन को रेफर किया जाएगा। हमें यह प्रलक्षित नहीं हो रहा है कि अपीलार्थी व रेस्पोंडेंट के बीच का यह विवाद आर्बिट्रेशन को क्यों नहीं दिया जा सकता जबकि अंबिकाबाई इस फरवरी के समझौते की पार्टी नहीं थी । अंबिका बाई फरवरी 1953 के समझौते की पक्षकार नहीं थी, अतः उसने धारा 20 की दरख्वास्त के तहत उसे नहीं जोडा है पर यह भी कोई वजह नहीं है कि उपरोक्त विवाद आर्बिट्रेशन के समक्ष क्यों नहीं रेफर किया जा सकता है खास तौर से जबकि अंबिका बाई का हिस्से का कोई विवाद नहीं है, जबकि इसमें आर्बिट्रेशन ने अपीलार्थी व प्रत्यर्थी का विवाद निर्णीत होगा जिसमें से

अंबिकाबाई का हिस्सा जिस हद तक विवाद नहीं है उस हद तक छोड दिया जाएगा। यह प्रकरण अलग होता अगर अंबिकाबाई का हिस्सा भी विवादित होगा परंतु अंबिकाबाई के हिस्से की हद तक कोई विवाद नहीं है तो आर्बिट्रेटर अन्य पक्षकारों की हद तक निर्णीत किया जा सकता है जिसमें से अंबिकाबाई का चार प्रतिशत हिस्सा छोडा जाए। यह हमारी समझ से परे है कि पक्षकारों ने इस तरह के आर्बिट्रेशन को किस तरह से बनाया जबकि उनको ज्ञान है कि एक अन्य व्यक्ति का भी इसमें हित है परन्तु उसे छोड दिया गया। न्यायालय अपनी तरफ से पक्षकारों को उनके द्वारा चुने गये फॉर्म में नहीं भेज सकते जबकि एक और हितबद्ध व्यक्ति को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। हमारी राय में अनंत भले ही अंबिकाबाई के हित को रीप्रिजेंट नहीं कर सकता परन्तु यह कोई वजह नहीं है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज को प्रभावित नहीं किया जाए जो कि 27/02/1953 में पक्षकारों के बीच में तय हो गया था अतः अपीलार्थी द्वारा इस बिन्दु पर दिए गए तर्क अमान्य हैं,

RE(2) यह सही है कि प्रत्यर्थियों ने दरख्वास्त अंतर्गत धारा 20 के तहत निवेदन किया है कि 27/02/1953 वाले एग्रीमेंट को काेर्ट में दायर किया जाए एवं 20/10/1948 के एग्रीमेंट को जो कि इससे जुडा हुआ है आर्बिट्रेशन में पेश किया जाए । 05/05/1952 के समझौते के बारे में खास तौर से कुछ नहीं कहा गया है जबकि वह फरवरी 1953 के समझौते

में शामिल है। यह पहले से ही अंकित है कि मई 1952 का समझौता 1948 के समझौते को पुख्ता करता है। जब आर्बिट्रेटर पक्षकारों के मध्य मई 1952 के विवाद पर गौर करता है तो उसी रिलेवेंसिटी हद तक फरवरी वाला समझौता भी सुसंगत होगा, मई 1952 वाला समझौता बाबाजी की मृत्यु की वजह से तैयार हुआ यह मात्र 22 अक्टूबर 1948 का सप्लीमेन्ट्री है । इन हालातों में जब विवाद फरवरी 1953 के समझौते के तहत सपठित अक्टूबर 1948 के समझौते के तहत आर्बिट्रेशन को दिया गया है, आर्बिट्रेटर इनका जो पुख्ता करने वाला समझौता 1952 का था उसे भी देख सकेगा । इस बात से हम सहमत हैं कि मुसल्लिफ न्यायालय में की गई प्लीडिंग्स को विचारण न्यायालय द्वारा कठोरता से नहीं देखा जा सकता । जब ट्रायल कोर्ट आर्बिट्रेटर को मेटर रेफर कर सकता है साथ ही मई 1952 के समझौते को कंसीडर करने हेतु रेफर कर सकता है मई 1952 के समझौते को भी आर्बिट्रेटर द्वारा देखा जाएगा जो अक्टूबर 1948 के समझौते के तहत विवादित हुआ है । ऐसे हालातों में हमारी राय में यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्षकारों के द्वारा इच्छित रेफरेंस प्रकरण के ऊपर की गई कार्यवाही को छिन्न भिन्न कर देगा अतः अपीलार्थी द्वारा इस बिन्दु पर दिए गए तर्क भी अमान्य हैं।

RE(3) इस शीर्ष के तहत जिस विवाद को संदर्भित करने की मांग की गयी है वह मध्यस्थता खंड के अंतर्गत नहीं आता है हमारे द्वारा

मध्यस्थता खंड को निर्धारित कर लिया गया है, हमारी राय में वह बहुत ही व्यापक महत्व का है । हमारी राय में यह उन सभी विवादों के मध्यस्थता के संदर्भ में है जो 22/10/1948, 5/05/1952 एवं 27/02/1953 के समझौतों से उत्पन्न हुए हैं। इस संदर्भ में मध्यस्थ प्रदान करता है जो विवाद जंगल की कटाैति या अन्य विवाद में उत्पन्न होते हों। मध्यस्थता खंड की इस व्यापकता को देखते हुए संभवत: यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मामले में जो उठाये गये विवाद हैं वह मध्यस्थता खंड से बाहर हों। हालांकि इस संबंध मे क्लॉज 6 के शुरूआती शब्दों को माना गया है जो यह कहता है कि बिना समझौता बिना किसी को प्रतिकूल प्रभाव डाले किया जाता है, वह इसमें सम्मिलित है।

दिनांक 22.10.1948 और 5.5.1952 या खान बहादुर दिवकर के पैसे या जंगल काटने या किसी अन्य तरीके से निर्यात करने के संबंध में, इसका निर्णय वर्तमान कानून के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करके और उनके माध्यम से कराया जाना चाहिए।"

ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बाद अपीलकर्ता द्वारा जंगल काट दिया गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 1953 के अंतिम समझौते के पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए; फलस्वरूप उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 ने धारा 20 ए के तहत आवेदन दायर किया। अगस्त 1954 में अधिनियम के 20.

आवेदन में उत्तरदाताओं द्वारा सामने रखा गया मामला यह था कि अपीलकर्ता ने, हालांकि जंगल काटने का काम किया, 1953 के समझौते की शर्तों को पूरा नहीं किया और उत्तरदाताओं को रुक-रुक कर खातों के विवरण दिखाए। यह आरोप लगाया गया था कि खाते अद्यतित नहीं बनाए गए थे, और उत्तरदाताओं की मांग के बावजूद कि खाते अद्यतित किए जाने चाहिए, अपीलकर्ता ने ऐसा नहीं किया। उत्तरदाताओं ने यह भी मांग की कि बेचे जाने वाले बचे हुए सामान का निपटान सभी की सहमति से किया जाना चाहिए; लेकिन अपीलकर्ता इस पर भी सहमत नहीं था। प्रतिवादी को दिखाए गए खातों का विवरण पूर्ण और सही नहीं था। खातों के विवरण में माल का पूरा स्टॉक निधि नहीं होना था और डेबिट आइटम अतिरंजित प्रतीत होते थे और सही नहीं थे; और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता के साथ साझेदारी का व्यवसाय चलाना संभव नहीं था और उत्तरदाताओं के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक था और अपीलकर्ता को शेष स्टॉक को हटाने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए ताकि हेराफेरी से बचा जा सके। इसके लिए रिसीवर की नियुक्ति लंबित है। प्रत्यर्थीयों ने प्रार्थना की कि उनके और अपीलकर्ता के बीच 22 अक्टूबर, 1948 और 27 फरवरी, 1953 के समझौतों के संबंध में विवाद को संदर्भित करने के लिए फरवरी 1953 का समझौता अदालत में दायर किया जाना चाहिए और अदालत द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए।

अपीलार्थी द्वारा आवेदन का विरोध किया गया। 27 फरवरी, 1953 के समझौते को अपीलकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था; लेकिन यह तर्क दिया गया कि मध्यस्थ का कोई संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए और उस संबंध में कई आधारों का आग्रह किया गया था। इस अपील के प्रयोजनों के लिए उत्तरदाताओं के आवेदन के उत्तर में सभी आधारों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। हम केवल उन्हीं आधारों का उल्लेख करेंगे जिनका हमारे समक्ष आग्रह किया गया है और वे इस प्रकार हैं:-

(1) बाबाजी की विधवा अंबिकाबाई ने स्वीकार किया कि जंगल में उसका हिस्सा था और चूंकि वह आवेदन में पक्षकार नहीं थी, इसलिए मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं हो सकता था क्योंकि जंगल का पूरा विवाद मध्यस्थों के समक्ष नहीं होगा।

(2) उत्तरदाताओं ने अपने आवेदन में केवल यह चाहा कि 22 अक्टूबर, 1948 और 27 फरवरी, 1953 के समझौतों से उत्पन्न विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाए, लेकिन इसमें 5 मई, 1952 का समझौता शामिल नहीं था, और इसलिए कोई संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह एक टुकड़ों में संदर्भ होगा जिसके परिणामस्वरूप कार्रवाई का कारण विभाजित हो जाएगा।

(3) जिस विवाद को संदर्भित करने की मांग की गई थी वह मध्यस्थता की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता था।

(4) उत्तरदाताओं ने अपने आवेदन में अपीलकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे और यह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं करने का आधार था।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि उत्तरदाताओं ने बाद में रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन को अनुमति दे दी गई थी। अंततः, हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने धारा 20 के तहत आवेदन 20 दो मुख्य आधारों पर खारिज कर दिया। अर्थात्, (i) कि लेखांकन के मामले में आवश्यक सभी पक्ष धारा के तहत आवेदन के पक्षकार नहीं थे और (ii) ऐसे आरोप थे कि यह मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था।

दोबारा। (4). अब हम धोखाधड़ी के प्रश्न पर आते हैं। इस संबंध में अपीलकर्ता की ओर से तर्क यह है कि उसके खिलाफ धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसलिए यह ऐसा मामला नहीं है जिसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। की उपधारा (4). 20 में कहा गया है कि जहां कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है, अदालत समझौते को दायर करने का आदेश देती है और मध्यस्थ को संदर्भ का आदेश देती है। इसलिए यह इस उप-धारा के तहत एक अदालत के लिए खुला है, जहां समझौते को दायर करने का आदेश न देने और मध्यस्थ को संदर्भ न देने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया गया है। इस उप-धारा के शब्द अदालत में

इस बात पर विचार करने के लिए व्यापक विवेक छोड़ते हैं कि क्या समझौते को दाखिल करने का आदेश दिया जाना चाहिए और तदनुसार एक संदर्भ बनाया जाना चाहिए। सामान्य शब्दों में यह निर्धारित करना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है कि पर्याप्त कारण क्या होगा जो अदालत को समझौते को दाखिल करने का आदेश देने से इनकार करने का अधिकार देगा और इस प्रकार संदर्भ का आदेश देने से इनकार कर देगा। अदालत को प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्णय लेना होगा कि क्या समझौते को दाखिल करने का आदेश न देने और संदर्भ का आदेश न देने के लिए पर्याप्त कारण बताए गए हैं।

हालाँकि, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों को आम तौर पर अदालतों द्वारा समझौते को दायर करने का आदेश न देने और संदर्भ न देने के लिए पर्याप्त आधार माना गया है। वह इस संबंध में रसेल बनाम रसेल के प्रमुख मामले को रेफर करते हैं। वह दो भाइयों के बीच साझेदारी का मामला था जिसमें मध्यस्थता खंड था। एक भाई ने दूसरे को साझेदारी ख़त्म करने का नोटिस दे दिया। इसके बाद दूसरे भाई ने धोखाधड़ी के विभिन्न आरोपों का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की और दावा किया कि नोटिस को शून्य घोषित किया जाना चाहिए और साझेदारी के विघटन की कोई घोषणा नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद जिस भाई पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था,

उसने अनुरोध किया कि मामले को मध्यस्थता खंड के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा जाए। इसका विरोध किया गया और अदालत ने कहा कि "ऐसे मामले में जहां धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, अदालत आम तौर पर विवाद को मध्यस्थता में भेजने से इनकार कर देगी यदि धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया पक्ष सार्वजनिक जांच चाहता है। लेकिन जहां मध्यस्थता पर आपत्ति धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली पार्टी द्वारा की जाती है, तो अदालत जरूरी नहीं कि इसे स्वीकार करेगी, जब तक कि धोखाधड़ी का प्रथम दृष्टया मामला साबित न हो जाए।

यह मामला निश्चित रूप से बताता है कि जहां धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाते हैं, वह पक्ष जिसके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, मध्यस्थता के संदर्भ का सफलतापूर्वक विरोध कर सकता है।

इस मामले की आपत्ति का पालन चार्ल्स ओसेंटन एंड कंपनी बनाम जॉनस्टन में किया गया। उस मामले में संपत्ति एजेंटों और सर्वेक्षणकर्ताओं की एक फर्म ने धारा के तहत एक आधिकारिक रेफरी के संदर्भ का विरोध किया। 1925 के न्यायिक अधिनियम के 89। किसी आधिकारिक रेफरी के निर्णय पर अपील या अन्यथा कानून के किसी बिंदु को छोड़कर, जैसा कि एस द्वारा प्रदान किया गया है, प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। न्याय प्रशासन अधिनियम, 1932 का 1। इसलिए फर्म ने तर्क दिया कि चूंकि उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा शामिल थी, इसलिए मामले को आधिकारिक रेफरी के

पास नहीं भेजा जाएगा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना कि चूंकि अपीलकर्ताओं की पेशेवर प्रतिष्ठा शामिल थी, इसलिए यह प्रश्न किसी आधिकारिक रेफरी की अपील के बिना अंतिम निर्णय पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि जूरी के साथ उच्च न्यायालय के सामान्य न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

एसबी के अंतर्गत आने वाले मामलों के संदर्भ में भारत में भी इन मामलों के सिद्धांत का पालन किया गया है। अधिनियम के 20 और 34. (देखें, महाराजा सर महिंद्रा चंद्र नंदी बनाम एच.वी. लो एंड कंपनी लिमिटेड, नरसिंह प्रसाद बूबना बनाम धनराज मिल्स, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम फर्म विश्वधा घी व्यापार मंडल, सुधांगसु भट्टाचार्जी बनाम रूपलेखा पिक्चर्स।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां किसी पक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और जिस पक्ष पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है वह चाहता है कि मामले की सुनवाई खुली अदालत में की जानी चाहिए, यह अदालत के लिए मध्यस्थता का आदेश न देने का पर्याप्त कारण होगा। समझौता दाखिल करना होगा और संदर्भ नहीं देना होगा। लेकिन यह हर आरोप किसी प्रकार की बेईमानी का आरोप नहीं लगाता है, विशेष रूप से खातों के मामलों में, जो अदालत को मामले को उस मंच से बाहर ले जाने के लिए पर्याप्त होगा जिसे पार्टियों ने स्वयं चुना है। यह बात

हमारी समझ में रसेल के मामले के फैसले से भी स्पष्ट है। उस मामले में एक भाई द्वारा दूसरे के खिलाफ रचनात्मक और वास्तविक धोखाधड़ी के आरोप थे और इन्हीं परिस्थितियों में अदालत ने वो टिप्पणियां कीं जिनका हमने ऊपर उल्लेख किया है। फिर भी, रोल्स के विद्वान मास्टर ने पी पर फैसले के दौरान भी देखा। 476 इस प्रकार है:-

> "किसी मध्यस्थ के खाते के प्रश्नों को संदर्भित करना इस अनुबंध के दायरे से बाहर क्यों होना चाहिए, भले ही उन प्रश्नों में किसी भागीदार के पक्ष में बेईमानी के समान कदाचार शामिल हो? मुझे यह समझ में नहीं आता। मैं ऐसा नहीं कहता कई मामलों में जो मैं न्यायालय के समक्ष मामले की दूसरी शाखा में आऊंगा, न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, हस्तक्षेप करने से इंकार नहीं कर सकता है; लेकिन मुझे यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता है कि यह खंड था सभी प्रश्नों पर लागू करने का इरादा नहीं है, यहां तक कि एक या दूसरे पक्ष पर नैतिक बेईमानी या नैतिक कदाचार का आरोप लगाने वाले प्रश्न भी शामिल हैं।"

हमारी स्पष्ट राय है कि केवल इसलिए कि कुछ आरोप लगाए गए हैं कि खाते सही नहीं हैं या कि कुछ चीजें अतिरंजित हैं इत्यादि, अदालत को मध्यस्थता का संदर्भ देने से इनकार करने के लिए प्रेरित करने के लिए

पर्याप्त नहीं है। यह केवल गंभीर प्रकृति के धोखाधड़ी के आरोपों के मामलों में है कि अदालत मध्यस्थता समझौते को दायर करने का आदेश देने से इनकार कर देगी जैसा कि रसेल के मामले में तय किया गया था और कोई संदर्भ नहीं देगा। इस संबंध में हम मिनिफ़ी बनाम द रेलवे पैसेंजर्स एश्योरेंस कंपनी का संदर्भ ले सकते हैं। वहाँ प्रश्न यह था कि क्या कुछ कार्यवाहियों पर रोक लगा दी जानी चाहिए; और यह माना गया कि इस तथ्य के बावजूद कि मुद्दा और इसके समर्थन में सबूत कुछ निश्चित व्यक्तियों और उनके साथ उपस्थित लोगों के आचरण पर असर डाल सकते हैं और इसलिए इसमें धोखाधड़ी या कोई धोखाधड़ी के समान प्रश्न शामिल हो सकता है, वह था ठहरने से इंकार करने का कोई आधार नहीं। ऐसा तभी होता है जब धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जिसके लिए खुली अदालत में मुकदमा चलाया जाना वांछनीय है, तभी मध्यस्थता समझौते को दायर करने का आदेश देने से इनकार करना और संदर्भ देने से इनकार करना एक अदालत के लिए उचित होगा।

इसलिए आइए हम इस मामले में आरोपों की ओर मुड़ें और देखें कि उनकी प्रकृति क्या है। उन आरोपों में कहा गया है कि (i) खाते अद्यतित नहीं थे, और यहां तक कि उत्तरदाताओं की मांग पर भी, अपीलकर्ता ने उन्हें अद्यतित नहीं किया; (ii) अपीलकर्ता द्वारा दिखाए गए खातों के विवरण पूर्ण नहीं थे और सही प्रतीत नहीं होते थे; और (iii) माल का पूरा

स्टॉक उसमें नहीं पाया गया और डेबिट आइटम अतिरंजित और गलत प्रतीत हुए। आवेदन में खातों के संबंध में ये एकमात्र आरोप थे और हमारी राय में ये अपीलकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के गंभीर आरोप नहीं हैं, जिसके लिए खुली अदालत में मुकदमा चलाने की आवश्यकता होगी। खातों में प्रविष्टियों की शुद्धता या अन्यथा के बारे में ऐसे आरोप अक्सर लेखा मुकदमों में लगाए जाते हैं; लेकिन हमारी राय में ये धोखाधड़ी के इतने गंभीर आरोप नहीं हैं कि किसी अदालत को यह आदेश देने के लिए प्रेरित किया जाए कि मध्यस्थता समझौता दाखिल नहीं किया जाना चाहिए और कोई संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए। खातों के संबंध में इन आरोपों के अलावा उत्तरदाताओं ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता को स्टॉक हटाने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए ताकि रिसीवर की नियुक्ति होने तक उसके दुरुपयोग से बचा जा सके। वह गबन का वास्तविक आरोप नहीं था; इसमें केवल इतना कहा गया कि उत्तरदाताओं को डर था कि यदि निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई और रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया तो भविष्य में हेराफेरी हो सकती है। आगे रिसीवर की नियुक्ति के आवेदन के समर्थन में शपथ पत्र में उत्तरदाताओं ने लेखा-जोखा की स्थिति से अपने-अपने निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें जंगल की कटाई, तैयार माल, माल का सही और पूरा लेखा-जोखा नहीं मिला है। बेचा गया और माल अपीलकर्ता से शेष राशि में प्राप्त हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें

संदेह है कि उन्हें दिए गए खातों से उनके निष्कर्षों पर माल और धन का दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्हें दिखाए गए खातों में, चारकोल की बिक्री प्रचलित बाजार दर से बहुत कम दर पर दिखाई गई थी और इन परिस्थितियों में उत्तरदाताओं को आशंका थी कि यदि माल की बिक्री का काम अपीलकर्ता के हाथों में रहा तो , माल की वास्तविक कीमत का एहसास नहीं होगा। हालाँकि, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वास्तव में अपीलकर्ता ने अधिक कीमत पर सामान बेचकर और खाते में कम कीमत दिखाकर गुप्त लाभ कमाया था। उत्तरदाताओं ने अपनी आशंका के समर्थन में खाते में प्रविष्टियों की ओर इशारा किया, जिसमें बिक्री मूल्य की कम दर दिखाई गई थी कि यदि माल की बिक्री का काम अपीलकर्ता के हाथ में रहा तो भविष्य में वास्तविक कीमत प्राप्त नहीं होगी। इसलिए एस के तहत आवेदन का अवलोकन। 20 और रिसीवर की नियुक्ति के लिए आवेदन के समर्थन में दायर हलफनामा अपीलकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के किसी भी गंभीर आरोप का खुलासा नहीं करता है। इससे पता चलता है कि उत्तरदाता उन्हें सौंपे गए खातों से संतुष्ट नहीं थे और उन्हें संदेह था कि उन्होंने मामलों की सही और पूरी स्थिति का खुलासा नहीं किया है। इस तरह के आरोप, जैसा कि हमने पहले ही टिप्पणी की है, अक्सर खाता मुकदमों में लगाए जाते हैं और यदि वे किसी ऐसे मामले में मध्यस्थता समझौते के लिए खाता मुकदमे को संदर्भित नहीं करने के लिए

पर्याप्त आधार होते हैं जिसमें लेखांकन आवश्यक होगा तो मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। इसीलिए हम इस बात पर जोर देते हैं कि रसेल के प्रमुख मामले में भी, विद्वान मास्टर ऑफ द रोल्स को यह बताने में परेशानी हो रही थी कि खातों के मामले में यह जरूरी नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थता का कोई संदर्भ नहीं दिया जाना चाहिए, भले ही प्रश्न हों उन खातों से संबंधित, जिनमें किसी भागीदार की ओर से बेईमानी तक का कदाचार शामिल हो सकता है, मध्यस्थता की कार्यवाही में सामने आ सकता है और यहां तक कि ऐसे मामले जहां नैतिक बेईमानी या नैतिक कदाचार के लिए एक पक्ष या दूसरे को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है। हमें ऐसा लगता है कि हिसाब-किताब रखने के मामले में नैतिक बेईमानी या नैतिक कदाचार का संकेत देने वाला हर आरोप धोखाधड़ी के ऐसे गंभीर आरोप की श्रेणी में नहीं आएगा, जो अदालत को मध्यस्थता समझौते को दायर करने का आदेश देने से इनकार करने और ऐसा करने से इनकार करने के लिए मजबूर करेगा। संदर्भ। इस मामले में लगाए गए आरोपों को देखते हुए हमारी राय है कि इस मामले में धोखाधड़ी के ऐसे कोई गंभीर आरोप नहीं हैं जो अदालत के लिए यह कहने के लिए पर्याप्त होंगे कि विवाद को मध्यस्थता के लिए न भेजने के लिए पर्याप्त कारण हैं। इसलिए अपीलकर्ता का यह तर्क भी विफल होना चाहिए।

इसलिए अपील विफल हो जाती है और इसे जुर्माने सहित खारिज किया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपा गुर्जर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।